Family. Under Schemes for providing income generating assets like IRDP, there is earmarking of 40% of benefits for women. Allotment of houses under Indira Awas Yojana is made in the name of the female member or in the joint name of husband and wife.

श्रीमती वीणा वर्मा: मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि जिस तरह से आपने कहा है कि महिलाओं को सम्पत्ति के स्वामित्व के बारे में विश्व भर में जो अधिकार है। उसमें 10 प्रतिशत से भी कम उनके स्वामित्व में है और आय अर्जित करने वालों में भी 10 प्रतिशत है। लेकिन भारतीय महिलाओं की स्थिति यह है कि पहले तो वह बेटी है, फिर पत्नी, अगर वह विधवा है तो उसको इसका अधिकार है। लेकिन अधिकतर भारतीय औरतें अपने को अधिक सौभाग्यवती समझती हैं अगर वह पति के घर में सदा सुहागिन रहे। उसको बेटी के रूप में संपत्ति में अधिकार हैं लेकिन पत्नी के रूप में पति की सम्पत्ति का कोई अधिकार नहीं है जब तक कि उसका पति जीवित है। विधवा को पति की सम्पत्ति पाने का अधिकार है। महिलाओं को खेती में अधिकार नहीं है, एनसेस्ट्रल प्रापर्टी में अधिकार नहीं है। पत्नी को यह अधिकार नहीं है, बेटी को बेटी के रूप में संपत्ति पाने का अधिकार है। तो क्या औरतें अपनी सारी जिंदगी बेटी बने रहने की सोचें या फिर जो उसके सारे जीवन की साधना कि वह सौभाग्यवती रहना चाहती है, इक्वल पार्टनर कहलाती है, अर्धांगिनी है तो क्या पति की सपंत्ति में, शादी एक कानूनी प्रक्रिया भी है और यह पवित्र होने के अलावा..

श्री सभापति: आपका सवाल हो गया।

श्रीमती वीणा वर्मा: तो क्या महिलाओं को पति की चल-अचल सम्पत्ति में शादी के दिन से बराबर का स्वामित्व देने के बारे में विचार करें और संविधान संशोधन का कोई प्रस्ताव लायेंगे?

डा० मुरली मनोहर जोशी: संविधान के अनुसार तो हर एक व्यक्ति को बराबरी का अधिकार कई प्रकार से है। संविधान के अनुसार किसी भी तरह से जेंडर का डिसक्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ऐसी इसमें व्यवस्था है। लेकिन जो सम्पत्ति के उत्तराधिकार का कानून है उसमें संशोधन की हमने बार-बार राज्य सरकारों को हिदायतें दी है। कुछ राज्य सरकारों ने अपने यहां हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में परिवर्तन भी किया है, संशोधन भी किया है। इसी तरह से जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, हम इन तमाम प्रश्नों और इन तमाम समस्याओं के बारे में एक सुविचारित राय जानने के लिए उसको कहते रहते है। हमारा मंत्रालय प्रस्तावों को विभिन्न मंत्रालयों तक भेजता है। लेकिन ...**(व्यवधान)**... मेरी पूरी बात सुनिए आप इतनी जल्दी में क्यों हैं?

हमने राष्ट्रीय महिला आयोग को बार-बार यह लिखा है, अन्य मंत्रालयों को कहते रहते हैं। हमारा मंत्रालय इस काम को अंजाम देने वाला मंत्रालय नहीं है। यह इन तमाम समस्याओं को एकत्रित करके विभिन्न मंत्रालयों को पहुंचाने वाला है। हमारी सिफारिश इस मामले में यह रही है कि उत्तराधिकार कानून में संशोधन किए जाएं और महिलाओं को सम्पत्ति के मामले में अधिकार दिए जाएं जो मंशा संविधान की उनको देने की है। लेकिन इस कानून को लाने की व्यवस्था तभी होगी जब कि इस पर राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिशें और बाकी सिफारिशें हमारे पास आ जाएं।

The question was actually asked on the of the House by Shrimati Veena Verma.

उन पर सुविचारित अपना मन्तव्य हम प्रकट करेंगे। मंत्रालय की दृष्टि से महिलाओं को बराबर का अधिकार मिलना उचित है।

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

MISS MABEL REBELLO: Sir this is an important question. We want a Half-an-hour Discussion on it.

MR. CHAIRMAN: You please give notice. We will have a Half-an-hour Discussion.

श्रीमती कमला सिन्हा: सर, इस पर एक बहस हो जानी चाहिए।

श्री सभापति: हां, मैंने कहा है कि आप एक हाफ एन आवर का नोटिस दीजिए।

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Increase in HIV afflicted Persons in the Country

*441. DR. MOHAN BABU: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there has been a sharp increase in HIV-AIDS case all over the country;

(b) whether it is also a fact that a national survey was conducted by the National AIDS Control Organisation (NACO) under the aegis of the Ministry of Health and Family Welfare during February-March this year;

(b) if so, the details thereof and the percentage of people afflicted with disease in Andhra Pradesh; and

(b) the steps taken by Government to create awareness about the disease?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI DALIT EZHILMALAI):

(a) No, Sir.

(b) and (c) Yes, Sir. The results of the National Survey in Andhra Pradesh are as follows:

HIV prevalence among STD Clinic attenders at Hyderabad 24.4% Vizag-24.7% and Tirupati-15.6%

HIV prevalence among Ante-natal clinic attenders at Hyderabad — 1.5% and Guntur-2.0%

(d) information Education and Commission (IEC) is an important thrust area for the prevention and Control of HIV/AIDS and the Government has taken a number of steps to create awareness and bring about behaviour change.

- A National campaign had been launched through the mass media viz. Doordarshan, AIR, Print media on the national networks and regional chennels to create awareness among the general public.
- Greater emphasis is being given to creating awareness in rural areas through folk media, local troupes, street plays etc.
- An intensive programme had been taken up to provide information and counselling services through centres run by NGOs. This includes the setting up of the National AIDS Telephone Hotline.
- A number of NGOs have been given financial and technical support to take up targeted intervention programmes in high risk behaviour groups such as sex workers, intravenous drug users, truckers, street children, migrant labour etc.
- A National plan has been launched for education and sensitisation of youth through a school based programme. College youth are being sensitised through the NSS activities.
- For non-student and rural youth, programmes are being launched through the Nehru Yuvak Kendras.

Plan to provide Food to Hunger Sticken people

*442. SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL: Will the Minister of FOOD AND CONSUMER AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Human Rights Commission has given mandate to Orissa Government to provide one time food to seventy six thousand persons everyday who are living below poverty line and are hunger affected;

(b) how many hunger sticken persons are there in the country;

(c) whether the Central Government has a plan to provide one time food to hunger sufferers;

(b) if not, when Government intends to provide the same to them; and

(c) whether the Ministry of Food and Consumer Affairs will provide necessary foodgrains free of cost to States for the said purpose or at concessional rates?